

न्यूज टुडे

CCUS के माध्यम से नेट जीरो लक्ष्यों को सक्षम करने के लिए अपनी तरह का पहला R&D रोडमैप लॉन्च किया गया

इस रोडमैप को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने तैयार किया है। यह रोडमैप कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) में तीन चरणों वाला अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम प्रदान करता है।

तीन चरणों में निम्नलिखित शामिल हैं

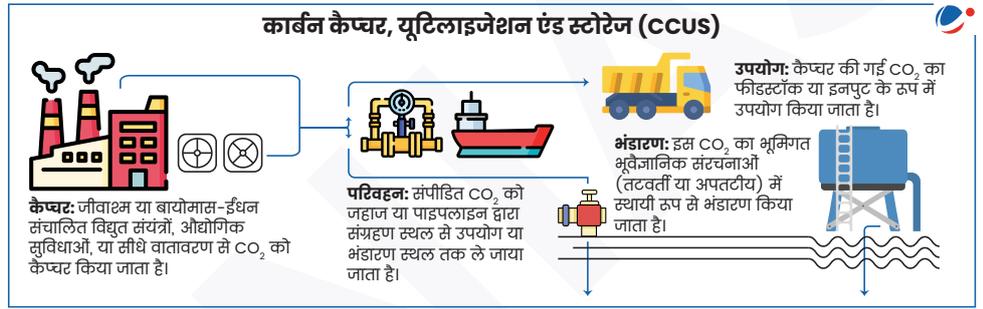
- ▶ पहला चरण: उत्सर्जन करने वाले मौजूदा उद्योगों में एंड-ऑफ-पाइप (EP) समाधान के रूप में वर्तमान अत्याधुनिक CCUS प्रौद्योगिकियों या उनके बेहतर संस्करणों का एकीकरण किया जाएगा।
- ▶ दूसरा चरण: CCUS अनुपालन डिज़ाइन (CCD) का उपयोग करके नए औद्योगिक विनिर्माण संयंत्रों में उन्नत CCUS प्रौद्योगिकियों का एकीकरण किया जाएगा।
- ▶ तीसरा चरण: नवीन कम उत्सर्जन करने वाली औद्योगिक विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में फोटो-बायो-इलेक्ट्रो-कैटेलिटिक रूपांतरण जैसी उभरती CCUS प्रौद्योगिकियों का एकीकरण किया जाएगा। यह एकीकरण CCUS इन वन पॉट (COP) रणनीति के रूप में किया जाएगा।

CCUS के बारे में

ये वे प्रौद्योगिकियां हैं, जो विद्युत संयंत्रों जैसे बड़े उत्सर्जन स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन को कम करने, या वातावरण से मौजूदा CO₂ को हटाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। साथ ही, ये प्रौद्योगिकियां हटाई गई CO₂ को समुद्री जल, गहरे समुद्र तलछट, या भूवैज्ञानिक स्थलों आदि में संग्रहीत करने में सक्षम भी बनाती हैं।

जलवायु परिवर्तन को कम करने में CCUS की भूमिका

- ▶ 'हार्ड टू एवेट' उद्योगों में उत्सर्जन को कम करना: CCUS मुख्य रूप से उन उद्योगों के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है, जिनका विकारणीकरण करना कठिन (हार्ड टू एवेट) होता है। इन उद्योगों में लौह-इस्पात, रसायन आदि उद्योग शामिल हैं।
- ▶ निम्न कार्बन उत्सर्जन के साथ विद्युत और हाइड्रोजन का उत्पादन: CCUS को कोयला, गैस, बायोमास या अपशिष्ट पर संचालित होने वाले विद्युत संयंत्रों पर स्थापित किया जा सकता है।
- ▶ वातावरण से मौजूदा CO₂ को हटाना: या तो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ जैव-ऊर्जा (BECCS) या डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज (DACCS) के माध्यम से। इन दोनों का तकनीकी आधार CCUS है।
 - ⊕ DACCS तकनीक वातावरण से सीधे CO₂ को कैप्चर करने में सक्षम बनाती है।
 - ⊕ BECCS तकनीक शुद्ध आधार पर CO₂ को हटाने में परिणाम उत्पन्न कर सकती है। इसमें बायोमास को संधारणीय रूप से प्राप्त किया जाता है।



नीति आयोग और आईबीएम ने वर्ष 2047 तक भारत को विश्व की शीर्ष तीन क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए रोडमैप जारी किया

यह रोडमैप "भारत को क्वांटम-संचालित अग्रणी अर्थव्यवस्था में रूपांतरण (Transforming India into a leading Quantum-Powered Economy)" शीर्षक से जारी किया गया।

- ▶ इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम विकसित करना और वैश्विक क्वांटम बाज़ार में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करने में मदद करना है।
- ▶ इसका लक्ष्य भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कम से कम 10 क्वांटम स्टार्टअप को विकसित करना है। इनमें से प्रत्येक स्टार्टअप का राजस्व 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा। साथ ही, 2035 तक वैश्विक क्वांटम सॉफ्टवेयर एवं सर्विसेज बाज़ार मूल्य में इनकी 50% से अधिक हिस्सेदारी होगी।

भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति

- ▶ प्रतिभागियों की संख्या: भारत में क्वांटम-संबंधित क्षेत्रों में स्नातक विद्यार्थियों की संख्या लगभग 91,000 है। इस मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। केवल यूरोपीय संघ (EU) ही भारत से आगे है।
- ▶ राज्य-स्तरीय प्रतिस्पर्धा: विभिन्न राज्य अपने-अपने क्वांटम इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए:
 - ⊕ कर्नाटक ने क्वांटम रिसर्च पार्क (QuRP) स्थापित किया है।
 - ⊕ आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अमरावती क्वांटम वैली (AQV) लॉन्च किया है।

रोडमैप में की गई मुख्य सिफारिशें

- ▶ क्वांटम कार्यबल को बढ़ाना: अगले 2-3 वर्षों में वैज्ञानिक, जटिल इंजीनियरिंग और उद्योग में कार्य करने के लिए कुशल पेशेवर कार्यबल तैयार करना चाहिए।
- ▶ क्वांटम के लिए शीर्ष 3-5 अवसर क्षेत्रों को प्राथमिकता देना: सुरक्षित संचार, स्वास्थ्य-देखभाल एवं फार्मा, क्रायोजेनिक्स, वित्तीय सेवाएँ, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रक।
- ▶ लैब के शोध के बाद प्रौद्योगिकी के बाज़ार में प्रवेश की प्रक्रिया को तेज करना: दो वर्षों के भीतर अनुसंधान, प्रौद्योगिकी के प्रमाणीकरण और लैब से बाज़ार तक प्रौद्योगिकी को पहुंचाने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल और तेज़ बनाने की आवश्यकता है।
- ▶ वैश्विक मानक-निर्धारण में नेतृत्व प्रदान करना: भारत को मानक-निर्धारण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और क्वांटम प्रौद्योगिकी से संबंधित वैश्विक मानकों के निर्माण का नेतृत्व करना चाहिए। इससे भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा।
- ▶ भारतीयों द्वारा स्थापित स्टार्टअप के लिए भारत को आकर्षक बनाना: इससे 90% से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप भारत में ही पंजीकृत रहने को प्राथमिकता देंगे और उन्हें विदेश पलायन करने से रोकने में मदद मिलेगी।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में

- ▶ परिभाषा: क्वांटम प्रौद्योगिकी वह तकनीक है, जो क्वांटम यांत्रिकी (उप-परमाण्विक कणों की भौतिकी) पर आधारित सिद्धांतों का उपयोग करती है। क्वांटम यांत्रिकी में शामिल हैं: क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोज़िशन।
- ▶ यह चार प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत है:
 - ⊕ क्वांटम कंप्यूटिंग
 - ⊕ क्वांटम संचार {जैसे क्वांटम कुंजी वितरण (QKD)}
 - ⊕ क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलाजी
 - ⊕ क्वांटम पदार्थ।

खाद्य-पदार्थ किरणन (Food irradiation) एक सुरक्षित खाद्य-प्रसंस्करण तकनीक है

उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्यों से हुई है। खाद्य-पदार्थ किरणन तकनीक में किसी भी प्रकार की विषाक्तता, पोषण संबंधी या सूक्ष्मजीव संक्रमण संबंधी समस्याएं सामने नहीं आई हैं।

- इस तकनीक को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन सहित कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं का अनुमोदन प्राप्त है।
- ‘खाद्य-पदार्थ किरणन’ के बारे में
 - यह एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें पहले से पैक या थोक मात्रा में खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों को निर्धारित मात्रा वाली विकिरणीय ऊर्जा (Radiant energy) के संपर्क में लाया जाता है। इसका वांछित उद्देश्य खाद्य पदार्थों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना और उनकी शेल्फ-लाइफ बढ़ाना है।
 - ⊕ उदाहरण के लिए: रेडियोलिसिस प्रक्रिया के तहत खाद्य पदार्थों और कीट/रोगजनकों की कोशिकाओं के जल के अणु आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने पर रासायनिक रूप से विघटित हो जाते हैं। इससे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
 - ◆ गौरतलब है कि जल खाद्य पदार्थों और कीट/रोगजनकों की कोशिकाओं का मुख्य घटक है।
- महत्व: यह तकनीक:
 - ⊕ खाद्य पदार्थों में अंकुरण को रोकती है
 - ⊕ पकने (ripening) को विलंबित करती है
 - ⊕ कीट, परजीवी, रोगजनक और नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करती है
 - ⊕ साथ ही, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को संरक्षित रखती है।
- आयनकारी विकिरण (Ionizing Radiations) दो मूल प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करती हैं:
 - ⊕ प्राथमिक प्रक्रियाएं: इसमें ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूपांतरण और अवशोषण से आयनों या उत्तेरित अणुओं का निर्माण होता है।
 - ⊕ द्वितीयक प्रक्रियाएं: इसमें प्राथमिक घटनाओं से उत्पन्न उत्पादों की परस्पर अभिक्रिया से होने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये जल की मात्रा, ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ का pH मान जैसे चर (variables) से प्रभावित होते हैं।
- प्राथमिक और द्वितीयक प्रक्रियाओं से तैयार उत्पादों को विकिरण-अपघटित यानी रेडियोलिटिक उत्पाद कहा जाता है। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में लगभग नगण्य रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है।

भारत में ‘खाद्य-पदार्थ किरणन’ तकनीक

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ‘बहु-उत्पाद खाद्य-पदार्थ किरणन’ इकाइयों की स्थापना हेतु प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) की एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन योजना) उप-योजना के तहत सहायता प्रदान करता है।
- अगस्त 2025 तक बहु-उत्पाद खाद्य-पदार्थ किरणन इकाइयों की स्थापना हेतु 16 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 9 इकाइयां चालू हो चुकी हैं।

खाद्य-पदार्थ किरणन में प्रयुक्त विकिरण प्रकार



गामा किरणें

- कोबाल्ट-60 के रेडियोधर्मी रूपों से उत्पन्न होती हैं।
- भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (BRIT) खाद्य-पदार्थ किरणन के लिए कोबाल्ट-60 की आपूर्ति करता है।



एक्स-किरणें

- किसी लक्षित पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की उच्च-ऊर्जा धारा को खाद्य पदार्थों से परावर्तित करके बनाई जाती है।
- आमतौर पर औषधि निर्माण और उद्योग में इस्तेमाल होती है।



इलेक्ट्रॉन बीम

- यह उच्च-ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की धारा है, जो एक त्वरक (accelerator) से निकलती है। इसे खाद्य पदार्थों पर निर्देशित किया जाता है।
- यह त्वरित प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती है।

एक संसदीय समिति ने लोकपाल की जांच और अभियोजन शाखाओं के पूर्ण संचालन की मांग की

संसदीय समिति ने यह प्रकट किया है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के बावजूद, लोकपाल की जांच एवं अभियोजन (Prosecution) शाखाएं अपर्याप्त रूप से परिचालित हैं।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के बारे में

- यह अधिनियम कुछ लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने पर केंद्रित है। इसके लिए यह केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त के पदों की स्थापना को अनिवार्य करता है।
- इसमें निम्नलिखित की स्थापना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं:
 - ⊕ जांच शाखा (धारा 11): इसकी अध्यक्षता जांच निदेशक करता है। इसका कार्य लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध की प्रारंभिक जांच करना है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय है।
 - ⊕ अभियोजन शाखा (धारा 12): इसकी अध्यक्षता अभियोजन निदेशक करता है। इसका कार्य इस अधिनियम के तहत लोकपाल द्वारा सुनवाई की जा रही किसी भी शिकायत के संबंध में आरोपित लोक सेवकों का अभियोजन करना है।

संसदीय समिति की रिपोर्ट

- निष्कर्ष:
 - ⊕ जांच शाखा: अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन इसका पूर्ण संचालन अधूरा है।
 - ⊕ अभियोजन शाखा: अभी तक केवल बहुत कम मामले अभियोजन चरण तक पहुंचे हैं। इस प्रकार, एक पूर्ण विकसित पृथक शाखा अभी तक स्थापित नहीं की गई है।
- सिफारिशें: समिति ने दोहराया कि दोनों शाखाओं का पूर्ण गठन छह महीनों के भीतर किया जाना चाहिए। साथ ही, उसने जांच और अभियोजन दोनों शाखाओं को परिचालित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी आग्रह किया।

लोकपाल के बारे में

- लोकपाल की संरचना: लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं। इनमें से आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं।
- ⊕ अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या है, या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या है।
- ⊕ न्यायिक सदस्य वह व्यक्ति होता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या है।
- संरचना: लोकपाल के आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं में से होंगे।
- कार्यकाल या पदावधि: अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
- लोकपाल के व्यय: लोकपाल के प्रशासनिक व्यय (जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं) भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।
- लोक सेवक के खिलाफ शिकायत निम्नलिखित द्वारा दर्ज की जा सकती है: व्यक्ति, सोसायटी, व्यक्तियों का संघ, ट्रस्ट, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी (LLP), वैधानिक बोर्ड, निगम, वैधानिक प्राधिकरण आदि।

भारत में 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की स्थिति 2025' रिपोर्ट जारी की गई

यह रिपोर्ट आईआईएम बैंगलोर के सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक गुड्स ने तैयार की है। इसमें यह तर्क दिया गया है कि भारत ने एक "मध्यम-मार्ग" डिजिटल मॉडल बनाया है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को संतुलित करेगा तथा ग्लोबल साउथ के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करेगा।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के बारे में

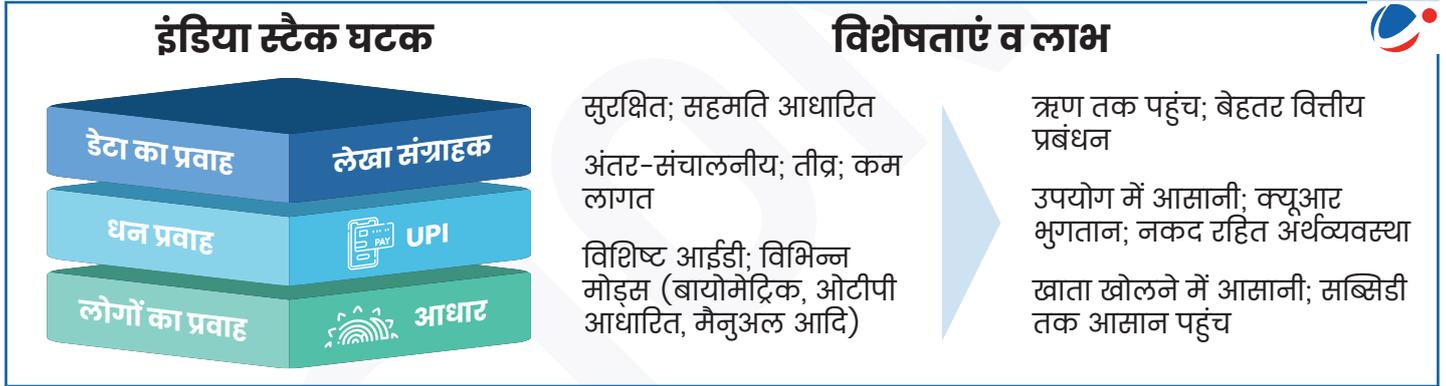
- ▶ यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक अवसंरचना-आधारित दृष्टिकोण है जो प्रौद्योगिकी, बाजार और शासन को समाहित करने वाले एक तंत्र के माध्यम से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है।
- ▶ इसमें लोक हित में खुले मानकों और विशिष्टताओं पर निर्मित साझा डिजिटल प्रणालियां शामिल हैं।
- ▶ किसी पहल के DPI के रूप में संचालित होने के लिए शर्तें:
 - ⊕ पहुंच और पैमाना: तीसरे पक्ष को नवाचार करने और विविध अंतिम सेवाएं प्रदान करने के लिए अवसंरचना का एक निर्माण खंड (building block) के रूप में उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
 - ⊕ गैर-अनन्यता का सिद्धांत: अवसंरचना गैर-भेदभावपूर्ण प्रकृति की और डिजाइन से समावेशी होनी चाहिए।
- ▶ महत्व:
 - ⊕ वित्तीय समावेशन (जन धन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी) में सहायक; सार्वजनिक सेवा वितरण (उदाहरण के लिए- DPI सक्षम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) में उपयोगी; नवाचार; नागरिकों का सशक्तीकरण का साधन आदि।

भारत के DPI के संबंध में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ▶ सह-निर्माण मॉडल: सरकार द्वारा संचालित और निजी क्षेत्रक द्वारा सक्रिय। उदाहरण के लिए- UIDAI का आधार तंत्र निजी नामांकन एजेंसियों, बायोमेट्रिक उपकरण निर्माताओं आदि के साथ साझेदारी करता है।
- ▶ निर्माण खंड दृष्टिकोण: तीव्र गति से व बाधारहित रीति से सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए DPI व डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPG) को एकीकृत किया गया है।
 - ⊕ उदाहरण के लिए- डिजीयात्रा (Digiyaatra) (DPG या तकनीकी परिसंपत्ति/ ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर) आधार (DPI) का उपयोग करके कागज रहित यात्रा अनुभव प्रदान करता है।
- ▶ विविध क्षेत्रों में विस्तार: भारत की विकास रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य करना। उदाहरण के लिए- कृषि (Agri-stack), लॉजिस्टिक्स (ULIP), और शिक्षा (DIKSHA)।

भारत का DPI तंत्र: इंडिया स्टैक

इसमें तीन मुख्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं- विशिष्ट पहचान, बेहतर भुगतान प्रणाली, और डेटा एक्सचेंज।



अन्य सुर्खियां



यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (OSCE)

यूक्रेन ने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (OSCE) में कहा है कि वह रूस के साथ 'वास्तविक शांति चाहता है, तुष्टीकरण नहीं'।

OSCE के बारे में (सचिवालय: वियना)

- ▶ यह विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है।
- ▶ भागीदार देश: उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के 57 देश (भारत सदस्य नहीं है)।
 - ⊕ सभी भागीदार देशों की समान स्थिति है और निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।
- ▶ शासनादेश (Mandate): यह एक अरब से अधिक लोगों के लिए स्थिरता, शांति और लोकतंत्र के लिए कार्य करता है। यह साझा मूल्यों के बारे में राजनीतिक संवाद और स्थायी बदलाव लाने वाले व्यावहारिक कार्यों के माध्यम से अपना यह कार्य संपन्न करता है।
- ▶ शासन संरचना: शिखर सम्मेलन (निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय), सुरक्षा सहयोग के लिए मंच (सुरक्षा के राजनीतिक-सैन्य आयाम से संबंधित) आदि।



अफार क्षेत्र

वैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का विश्लेषण करने के लिए अफार क्षेत्र को चुना। अफार क्षेत्र के बारे में

- ▶ यह इथियोपिया के पूर्वोत्तर भाग को कवर करता है, जहां लाल सागर अदन की खाड़ी से मिलता है।
- ▶ यहां तीन भ्रंश प्रणालियों का अभिसरण होता है, जो एक त्रिसंगम बनाती हैं। ये हैं- मुख्य इथियोपियाई, लाल सागर और अदन की खाड़ी भ्रंश।
- ▶ अफार अवसाद या दुनाकिल अवसाद: यह उत्तरी भाग का निर्माण करता है। यह बड़े पैमाने पर उथली खारी झीलों और ज्वालामुखियों वाला एक रेगिस्तानी झाड़ीयुक्त क्षेत्र है।
- ▶ अवाश नदी घाटी: यह दक्षिणी भाग बनाती है।
- ▶ इस क्षेत्र का अधिकांश भाग समुद्र तल से नीचे है और यह पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है।
- ▶ यह 'लूसी' सहित शुरुआती होमिनिड जीवाश्मों के लिए विख्यात है, जो एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेन्सिस (Australopithecus afarensis) प्रजाति थी।



गरुड़ शक्ति

अभ्यास गरुड़ शक्ति हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्पेशल फोर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ।

अभ्यास गरुड़ शक्ति के बारे में

- ▶ प्रकार: द्विपक्षीय।
- ▶ भागीदार देश: भारत-इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल।
- ▶ संस्करण: 10वां संस्करण।
- ▶ उद्देश्य: विशेष बलों के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतरसंचालनीयता को मजबूत करना।



ध्रुवा (DHRUVA)

डाक विभाग ने भारत में “एड्रेस एज ए सर्विस” (Address as a Service: AaaS) को सक्षम करने के लिए एक डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली बनाने की पहल के रूप में ध्रुवा (DHRUVA) का प्रस्ताव किया।

ध्रुवा (DHRUVA) के बारे में

- ▶ इसका पूर्ण रूप है “डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस” (Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address)।
- ▶ यह एक अंतरसंचालनीय, मानकीकृत और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली है।
- ▶ उद्देश्य: टेक्स्ट एड्रेस को UPI जैसे डिजिटल लेबल (जैसे- “नाम@एंटिटी”) से प्रतिस्थापित करना, जो भौतिक पत्तों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करेंगे।
- ▶ यह कैसे काम करता है: उपयोगकर्ता पूर्ण विवरण टाइप करने की बजाय एक एड्रेस लेबल साझा करेंगे तथा कंपनियां उपयोगकर्ता की सहमति से पूर्ण पते एवं निर्देशांकों को तुरंत एक्सेस कर सकेंगी।
- ▶ आधारभूत परत- DIGIPIN: यह 10-अंकीय अलफ़ा-न्यूमेरिक कोड है। यह कोड भारत की भौगोलिक सीमाओं में लगभग 4x4 मीटर के समान ग्रिड बनाकर भू-स्थान अवस्थिति (अक्षांश-देशांतर/ latitude-longitude) को दर्शाएगा।



महाइ सत्याग्रह

महाइ, भारत के पहले मानवाधिकार आंदोलनों में से एक का जन्मस्थान है। इस सत्याग्रह की शुरुआत डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने की थी।

महाइ सत्याग्रह के बारे में

- ▶ तिथि और स्थान: 20 मार्च 1927 को चावदार ताल, महाइ (महाराष्ट्र) में शुरू हुआ।
- ▶ उद्देश्य: जातिगत भेदभाव के कारण अस्पृश्यों को सार्वजनिक पेयजल तक पहुंच के अधिकार से वंचित किया जाता था। इसका उद्देश्य इस अधिकार को सुरक्षित करना था।
- ▶ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के प्रमुख सहयोगियों में आनंदराव चिले, बापू सहस्त्रबुद्धे, संभाजी गायकवाड़, रामचंद्र मोरे आदि शामिल थे।
- ▶ प्रतीकात्मक कार्य: अम्बेडकर और अन्य सत्याग्रहियों ने यह दावा करते हुए कि जल जैसे आवश्यक संसाधनों पर उच्च जातियों का एकाधिकार नहीं हो सकता सार्वजनिक हौज से पानी पिया।
- ▶ वैचारिक संदेश: जल एक बुनियादी मानवाधिकार है, न कि जातिगत विशेषाधिकार। इसका उद्देश्य अस्पृश्यता में निहित सामाजिक बहिष्कार को खंडित करना था।
- ▶ मनुस्मृति दहन: 25 दिसंबर 1927 को, अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया। इसके माध्यम से सांकेतिक रूप से जाति व्यवस्था को खारिज किया गया था।
- ▶ महत्त्व: यह अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों का पहला बड़ा नागरिक अधिकार आंदोलन था।



कार्तिगाई दीपम महोत्सव (Karthigai Deepam Festival)

तमिलनाडु में कार्तिगाई दीपम महोत्सव शुरू हुआ।

कार्तिगाई दीपम महोत्सव के बारे में

- ▶ यह कार्तिगाई (नवंबर-दिसंबर) के महीने में आने वाला तीन दिवसीय त्यौहार है।
- ▶ यह पूर्णिमा या पौर्णमी के दिन से शुरू होता है।
- ▶ इसमें मिट्टी के तेल के दीपक या अगल विलकू जलाए जाते हैं, ताकि बुरी आत्माओं को दूर किया जा सके।
- ▶ इसमें भगवान कार्तिकेय या भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है।
- ▶ इसका उल्लेख तमिल साहित्य ‘अहनानुरु’ में मिलता है, जो संगम साहित्य की महान कृतियों में से एक है।
- ▶ अच्चैयार (जो संगम युग की एक प्रसिद्ध महिला थीं) ने भी अपनी कविताओं में इसका उल्लेख किया है।



सीहॉक हेलीकॉप्टर

संयुक्त राज्य अमेरिका ने MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स के लिए \$946 मिलियन के सस्टेनमेंट पैकेज पर हस्ताक्षर करने के भारत के फैसले का स्वागत किया।

सीहॉक हेलीकॉप्टर के बारे में

- ▶ यह उन्नत हथियारों, सेंसर और एवियोनिक्स सुइट से सुसज्जित है तथा ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण है।
- ▶ यह अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 24-विमान विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध का हिस्सा है।
- ▶ विशेषताएं: इसे पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW), सतह-रोधी युद्ध (ASuW), खोज और बचाव (SAR), चिकित्सा निकासी (MEDEVAC) और ऊर्ध्वाधर पुनर्पूरति (VERTREP) के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ▶ महत्त्व: भारत की ब्लू-वॉटर यानी खुले समुद्र संबंधी क्षमताओं को बढ़ाना।



लार्ज एक्सपोजर्स फ्रेमवर्क (Large Exposures Framework-LEF) सीमाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी बैंकों के लिए उनकी विदेशी शाखाओं के संबंध में लार्ज एक्सपोजर्स फ्रेमवर्क (Large Exposures Framework: LEF) सीमाओं जैसे नियमों को सख्त किया है।

लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क (LEF) सीमाओं के बारे में

- ▶ LEF एक विवेकपूर्ण विनियमन है। इसका उद्देश्य संकेंद्रण जोखिम को नियंत्रित करना है। इसके लिए यह सीमित करता है कि कोई एकल उधारकर्ता या संबंधित उधारकर्ताओं का समूह एक बैंक से कितना उधार ले सकता है, या किसी बैंक का उन पर कितना एक्सपोजर हो सकता है।
- ▶ एक “लार्ज एक्सपोजर” को किसी प्रतिपक्ष (counterparty) (या संबंधित प्रतिपक्षों के समूह) को दिए गए ऐसे किसी भी एक्सपोजर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बैंक के पाल पूंजी आधार के 10% के बराबर या उससे अधिक हो।

RBI द्वारा हालिया बदलाव

- ▶ इसने LEF और अंतर-समूह लेनदेन और एक्सपोजर्स (Intragroup Transactions and Exposures: ITE) में संशोधन किया है। साथ ही, लार्ज एक्सपोजर्स और अंतर-समूह लेन-देनों की गणना के लिए कुछ पद्धतिगत मानदंडों को स्पष्ट किया है।
- ▶ इसने बैंकों से एकल प्रतिपक्षों, परस्पर जुड़े समूहों और विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित संकेंद्रण जोखिमों के प्रबंधन के लिए मजबूत नीतियां बनाने को भी कहा है।



तमिलनाडु के नए GI टैग वाले उत्पाद

तमिलनाडु ने भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों की अपनी सूची में पांच और उत्पाद जोड़े हैं।

नए GI उत्पादों में निम्नलिखित शामिल हैं

- ▶ वरैयूर सूती साड़ी: तिरुची जिले की मूल कारीगरी।
- ▶ कविंदपडी नट्टु सक्करै: एक गुड़ पाउडर।
- ▶ नमक्कल मक्कल पतिरंगल: सोपस्टोन (खड़िया पत्थर) के बर्तन।
- ▶ थूयामल्ली चावल की किस्म: थूयामल्ली का अर्थ है ‘शुद्ध चमेली’। यह 135 से 140 दिनों में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक साम्बा-सीज़न चावल की किस्म है।
- ▶ अम्बासमुद्रम चोप्पू सामान: लकड़ी के खिलौने।

GI टैग के बारे में

- ▶ GI टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति के कारण इन उत्पादों में विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- ▶ भारत में, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 GI के पंजीकरण व बेहतर संरक्षण का प्रावधान करता है।
- ▶ यह 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इस अवधि का नवीनीकरण कराया जा सकता है।

